

EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

3 - 9 MAY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: What is the new FDI limit notified by the Government of India in the insurance sector under the automatic route, and what is the FDI cap for LIC?

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र में अधिसूचित नई FDI सीमा क्या है और LIC के लिए FDI सीमा क्या है?

- A. 74% insurance; 20% LIC (74% बीमा; 20% LIC)
- B. 100% insurance; 49% LIC (100% बीमा; 49% LIC)
- C. 100% insurance; 20% LIC (100% बीमा; 20% LIC)
- D. 49% insurance; 20% LIC (49% बीमा; 20% LIC)
- E. 100% insurance; 26% LIC (100% बीमा; 26% LIC)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has notified 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the insurance sector under the automatic route under Foreign Exchange Management Act (FEMA).
- भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र में 100% FDI अधिसूचित किया है।
- This eliminates the need for an Indian joint venture partner for foreign insurers operating in India.
- इससे भारत में काम करने वाले विदेशी बीमाकर्ताओं के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदार की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- The 100% FDI limit also applies to insurance intermediaries such as brokers, reinsurance brokers, corporate agents, TPAs, surveyors, loss assessors, MGAs, and insurance repositories — subject to Insurance Regulatory and Development Authority of India norms.
- 100% FDI सीमा बीमा मध्यस्थों पर भी लागू होगी — भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों के अधीन।
- Foreign investment in Life Insurance Corporation of India will remain capped at 20% under a separate framework governed by the LIC Act, 1956 and Insurance Act, 1938.

- भारतीय जीवन बीमा निगम में विदेशी निवेश 20% तक सीमित रहेगा।
- Insurance companies with foreign investment must appoint at least one resident Indian citizen as Chairperson, MD or CEO, and comply with RBI pricing guidelines under FEMA.
- विदेशी निवेश वाली बीमा कंपनियों को कम से कम एक भारतीय निवासी को चेयरपर्सन/MD/CEO नियुक्त करना होगा और RBI के मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- The policy aligns with the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, which increased the FDI limit from 74% to 100%.
- यह नीति सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुरूप है, जिसने FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Sector — Insurance / क्षेत्र — बीमा
- FDI Limit (New) — 100% (Automatic Route)
- नई FDI सीमा — 100% (स्वचालित मार्ग)
- Previous FDI Limit — 74%
- पिछली FDI सीमा — 74%
- Route — Automatic Route under FEMA
- मार्ग — FEMA के तहत स्वचालित मार्ग
- Regulatory Body — Insurance Regulatory and Development Authority of India
- नियामक संस्था — IRDAI
- LIC FDI Cap — 20% (separate framework)
- LIC FDI सीमा — 20%
- Amendment Act — Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025
- संशोधन अधिनियम — सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025

Ques: Who has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI)?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया

है?

- A. Swaminathan Janakiraman / स्वामीनाथन जानकीरमण
- B. Rohit Jain / रोहित जैन
- C. Poonam Gupta / पूनम गुप्ता
- D. Shirish Chandra Murmu / शिरीष चंद्र मुर्मू
- E. T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India appointed Rohit Jain as Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of 3 years.
- भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिज़र्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया।
- His appointment is effective from May 3.
- उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी है।
- He was previously serving as an Executive Director at RBI.
- वे पहले RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे।
- He succeeds T. Rabi Sankar, who recently retired after completing his tenure.
- उन्होंने टी. रबी शंकर का स्थान लिया।
- After this appointment, RBI now has four Deputy Governors.
- इस नियुक्ति के बाद RBI में चार डिप्टी गवर्नर हैं।
- The four Deputy Governors are: Rohit Jain, Swaminathan Janakiraman, Poonam Gupta, Shirish Chandra Murmu.
- वर्तमान चार डिप्टी गवर्नर हैं: रोहित जैन, स्वामीनाथन जानकीरमण, डॉ. पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू।

Ques: Which UPI app became the first to cross 10 billion monthly transactions in March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 में कौन-सा UPI ऐप 10 बिलियन मासिक लेनदेन पार करने वाला

पहला ऐप बना?

- A) PhonePe / फोनपे
- B) Paytm / पेटीएम
- C) Google Pay / गूगल पे
- D) Amazon Pay / अमेज़न पे
- E) BHIM / भीम

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- PhonePe became the first UPI app to cross 10 billion monthly transactions, recording 10.50 billion transactions in March 2026.
- फोनपे मार्च 2026 में 10.50 बिलियन लेनदेन के साथ 10 बिलियन मासिक ट्रांजैक्शन पार करने वाला पहला UPI ऐप बना।
- This marks a major milestone in India's digital payments ecosystem.
- यह भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- As per data from National Payments Corporation of India, PhonePe held a 46.4% share by volume and 49.1% share by value.
- NPCI के अनुसार, फोनपे का वॉल्यूम में 46.4% और वैल्यू में 49.1% हिस्सा रहा।
- It processed transactions worth ₹14.48 lakh crore during the period.
- इस अवधि में ₹14.48 लाख करोड़ के लेनदेन प्रोसेस किए गए।
- The platform showed consistent growth, processing 8 billion transactions in December and 9.9 billion in January.
- प्लेटफॉर्म ने लगातार वृद्धि दिखाई, दिसंबर में 8 बिलियन और जनवरी में 9.9 बिलियन लेनदेन प्रोसेस किए।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- PhonePe Founded – 2015
- फोनपे की स्थापना – 2015
- Headquarters – Bengaluru

- मुख्यालय – बेंगलुरु
- UPI Regulator – National Payments Corporation of India (NPCI)
- UPI नियामक – नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
- Milestone – First app to cross 10 billion monthly transactions
- उपलब्धि – 10 बिलियन मासिक ट्रांजैक्शन पार करने वाला पहला ऐप

Ques: MuleHunter.AI tool, recently in news, has been developed by which institution?

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा MuleHunter.AI टूल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है?

- A) SEBI / सेबी
- B) NABARD / नाबार्ड
- C) Reserve Bank of India / आरबीआई
- D) SIDBI / सिडबी
- E) NPCI / एनपीसीआई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Ministry of Finance has instructed banks to adopt MuleHunter.AI, an AI-based tool developed by Reserve Bank of India.
- वित्त मंत्रालय ने बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित MuleHunter.AI टूल अपनाने का निर्देश दिया है।
- The tool is designed to identify and prevent mule accounts used in cyber-enabled financial frauds.
- यह टूल साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में उपयोग होने वाले म्यूल अकाउंट्स की पहचान और रोकथाम के लिए बनाया गया है।
- Financial Services Secretary M. Nagaraju advised banks to implement the tool

at the earliest.

- वित्तीय सेवा सचिव M. Nagaraju ने बैंकों को इस टूल को जल्द से जल्द लागू करने की सलाह दी।
- State Level Bankers' Committees (SLBCs) have also been asked to coordinate with state police authorities for cyber fraud prevention.
- State Level Bankers' Committees (SLBCs) को साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करने को भी कहा गया है।
- The initiative aims to strengthen digital banking security and fraud detection systems.
- इस पहल का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Reserve Bank of India Established – 1935
- RBI की स्थापना – 1935
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Ministry of Finance Headquarters – New Delhi
- वित्त मंत्रालय का मुख्यालय – नई दिल्ली
- Mule Account – A bank account used to transfer illegally obtained money
- म्यूल अकाउंट – ऐसा बैंक खाता जिसका उपयोग अवैध धन ट्रांसफर के लिए किया जाता है

Ques: Which bank has launched a Self Help Group (SHG) Savings Account to promote financial inclusion among women-led SHGs?

प्रश्न: महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु किस बैंक ने SHG सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) India Post Payments Bank / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India Post Payments Bank has launched a Self Help Group (SHG) Savings Account.
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने स्वयं सहायता समूह (SHG) सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है।
- The initiative aims to promote financial inclusion and empower women-led SHGs in rural areas.
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के SHGs को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

• **Key features of the account include:**

Zero balance account
No minimum balance requirement
Maximum balance limit of ₹2 lakh
No charges on deposits and withdrawals
Quarterly interest payments
One free account statement per month
No account closure charges

• **इस खाते की मुख्य विशेषताएं:**

जीरो बैलेंस खाता
न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं
अधिकतम बैलेंस ₹2 लाख
जमा और निकासी पर कोई शुल्क नहीं
तिमाही ब्याज भुगतान
प्रति माह एक मुफ्त स्टेटमेंट
खाता बंद करने पर कोई शुल्क नहीं

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- IPPB Launched – 1 September 2018
- IPPB लॉन्च – 1 सितंबर 2018
- Ownership – 100% Government of India
- स्वामित्व – 100% भारत सरकार
- Parent Department – Department of Posts, Ministry of Communications
- संबंधित विभाग – डाक विभाग, संचार मंत्रालय
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली

Ques: Who among the following were recently appointed as full-time members of NITI Aayog?

प्रश्न: निम्नलिखित में से हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Joram Aniya and R. Balasubramaniam / जोराम अनिया और आर. बालसुब्रमण्यम
- B) Sanjiv Khanna and Rajiv Gauba / संजीव खन्ना और राजीव गौबा
- C) Ashok Lahiri and Amit Shah / अशोक लाहिड़ी और अमित शाह
- D) M. Srinivas and Abhay Karandikar / एम. श्रीनिवास और अभय करंदीकर
- E) Suman Bery and K.V. Raju / सुमन बेरी और के.वी. राजू

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has appointed Dr. Joram Aniya and Dr. R. Balasubramaniam as full-time members of NITI Aayog.
- भारत सरकार ने डॉ. जोराम अनिया और डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।

- The appointments were approved by Prime Minister Narendra Modi.
- इन नियुक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूरी दी गई।
- With these appointments, the total number of full-time members in NITI Aayog has increased to seven, along with one Vice-Chairperson.
- इन नियुक्तियों के बाद नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या सात हो गई है, साथ में एक उपाध्यक्ष भी हैं।
- Dr. R. Balasubramaniam has earlier served in the Capacity Building Commission and is known as a scholar, author, and public policy expert.
- डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम पहले कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में कार्य कर चुके हैं।
- Dr. Joram Aniya is an academican from Arunachal Pradesh with over 18 years of experience in teaching, research, and public policy.
- डॉ. जोराम अनिया अरुणाचल प्रदेश की शिक्षाविद हैं।
- She is regarded as the first woman from the Nyishi community to earn a PhD and the first doctorate holder in Hindi from Arunachal Pradesh.
- उन्हें न्यीशी समुदाय की पहली महिला पीएचडी धारक और अरुणाचल प्रदेश से हिंदी में पहली डॉक्टरेट धारक माना जाता है।
- This is part of the major revamp of NITI Aayog announced in April 2026.
- यह अप्रैल 2026 में घोषित नीति आयोग के बड़े पुनर्गठन का हिस्सा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NITI Aayog Established – 1 January 2015
 - नीति आयोग की स्थापना – 1 जनवरी 2015
 - Headquarters – New Delhi
 - मुख्यालय – नई दिल्ली
 - Chairperson – Narendra Modi
 - अध्यक्ष – नरेंद्र मोदी
 - Vice-Chairperson – Ashok Lahiri
 - उपाध्यक्ष – अशोक लाहिड़ी
 - Replaced – Planning Commission
 - किसका स्थान लिया – योजना आयोग
-

Ques: Federal Bank is acquiring a credit card portfolio of around 4.5 lakh cards from which bank?

प्रश्न: Federal Bank लगभग 4.5 लाख कार्ड का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो किस बैंक से अधिग्रहित कर रहा है?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Citibank / सिटीबैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Federal Bank will acquire a selected India credit card portfolio from Standard Chartered Bank.
- Federal Bank भारत में Standard Chartered Bank के चयनित क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करेगा।
- The portfolio includes around 4.5 lakh (450,000) credit cards.
- इस पोर्टफोलियो में लगभग 4.5 लाख (450,000) क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
- The acquisition will help Federal Bank expand its customer base in major cities.
- यह अधिग्रहण फेडरल बैंक को बड़े शहरों में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में मदद करेगा।
- Federal Bank currently has around 8 lakh non co-branded cards and 13 lakh co-branded cards.
- फेडरल बैंक के पास वर्तमान में लगभग 8 लाख नॉन-को-ब्रांडेड कार्ड और 13 लाख को-ब्रांडेड कार्ड हैं।
- After this deal, Federal Bank's non co-branded credit card receivables are expected to increase by around 90%.
- इस डील के बाद फेडरल बैंक के नॉन-को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में लगभग 90% वृद्धि होने की उम्मीद है।

- The deal is expected to be completed within calendar year 2026.
- यह डील कैलेंडर वर्ष 2026 के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Federal Bank Established – 1931
- फेडरल बैंक की स्थापना – 1931
- Headquarters – Kochi, Kerala
- मुख्यालय – कोच्चि, केरल
- Standard Chartered Established – 1969
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्थापना – 1969
- Headquarters – London, United Kingdom
- मुख्यालय – लंदन, यूनाइटेड किंगडम

Ques: What is the key change in FDI norms announced by the Government of India in May 2026?

प्रश्न: मई 2026 में भारत सरकार द्वारा FDI नियमों में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है?

- A) Ban on Chinese investments / चीनी निवेश पर प्रतिबंध
- B) Allowing 10% Chinese stake firms via automatic route / 10% चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति
- C) Increase in FDI limit to 100% / FDI सीमा को 100% करना
- D) Removal of FEMA regulations / FEMA नियमों को हटाना
- E) Mandatory approval for all foreign investments / सभी विदेशी निवेश के लिए अनिवार्य मंजूरी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has eased FDI norms under Foreign Exchange Management Act for companies with up to 10% Chinese shareholding.
- भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी है।
- Such companies can now invest in India through the automatic route, subject to sectoral conditions.
- ऐसी कंपनियां अब क्षेत्रीय शर्तों के तहत ऑटोमैटिक रूट से निवेश कर सकती हैं।
- The decision came into effect from May 1, 2026, as notified by the Ministry of Finance.
- यह निर्णय 1 मई 2026 से वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होकर लागू हुआ।
- The relaxation is based on amendments to Press Note 3 of 2020 approved by the Union Cabinet of India.
- यह ढील 2020 के प्रेस नोट 3 में संशोधन पर आधारित है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
- It aims to boost foreign investment in sectors like electronics and manufacturing.
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाना है।
- However, the relaxation does not apply to entities registered in China, Hong Kong, or countries sharing land borders with India.
- हालांकि यह ढील चीन, हांगकांग या भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
- Higher or controlling Chinese stakes will still require government approval.
- अधिक या नियंत्रित हिस्सेदारी के लिए अभी भी सरकारी मंजूरी आवश्यक होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- FEMA Full Form – Foreign Exchange Management Act
- FEMA का पूर्ण रूप – विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
- Introduced – 1999
- लागू – 1999
- Nodal Ministry – Ministry of Finance
- संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
- DPIIT Full Form – Department for Promotion of Industry and Internal Trade

- DPIIT का पूर्ण रूप – उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- Press Note 3 Year – 2020
- प्रेस नोट 3 वर्ष – 2020

Ques: Under RBI's revised loan restructuring guidelines for disaster-hit areas, what is the mandatory provisioning requirement for banks and NBFCs?

प्रश्न: आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए RBI के संशोधित लोन पुनर्गठन दिशानिर्देशों के तहत बैंकों और NBFCs के लिए अनिवार्य प्रावधान (Provisioning) कितना है?

- A) 2%
- B) 3%
- C) 5%
- D) 7%
- E) 10%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India has introduced revised guidelines for loan restructuring in disaster-hit areas, providing greater flexibility to banks and NBFCs.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन पुनर्गठन के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे बैंकों और NBFCs को अधिक लचीलापन मिलेगा।
- The new framework will come into effect from 1 July 2026.
- यह नया ढांचा 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
- It allows lenders to proactively restructure loans without waiting for borrower requests.
- इसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही ऋण पुनर्गठन कर सकते हैं।
- A key feature is the mandatory 5% provisioning requirement, where lenders must set aside 5% of the outstanding loan value.
- इसका प्रमुख प्रावधान 5% अनिवार्य प्रावधान है, जिसमें ऋणदाताओं को बकाया ऋण

का 5% अलग रखना होगा।

- Borrowers have a 135-day opt-out window from the date of disaster declaration.
- उधारकर्ताओं को आपदा घोषणा की तिथि से 135 दिनों का ऑफ्ट-आउट विकल्प मिलेगा।
- RBI rejected requests to reduce provisioning to 2%, citing the need for better risk coverage in uncertain recovery scenarios.
- RBI ने प्रावधान को 2% करने के अनुरोध को अस्वीकार किया, यह कहते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में जोखिम कवर जरूरी है।

Eligibility conditions include:

- Only standard accounts are eligible
- Loans should not be overdue by more than 30 days at the time of disaster
- Also the requests to extend eligibility up to 89 days overdue were rejected to ensure that the relief targets genuine disaster-affected borrowers.

पात्रता शर्तें:

- केवल स्टैंडर्ड खाते पात्र होंगे
- आपदा के समय ऋण 30 दिनों से अधिक ओवरड्यू नहीं होना चाहिए
- साथ ही, बकाया ऋण के लिए पात्रता को 89 दिनों तक बढ़ाने के अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राहत का लाभ आपदा से वास्तविक रूप से प्रभावित उधारकर्ताओं को ही मिले।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Effective Date – 1 July 2026
- प्रभावी तिथि – 1 जुलाई 2026
- Provisioning Requirement – 5%
- प्रावधान आवश्यकता – 5%
- Opt-out Window – 135 days
- ऑफ्ट-आउट अवधि – 135 दिन
- Eligibility – Standard Accounts (≤ 30 days overdue)

- पात्रता – स्टैंडर्ड खाते (30 दिन से कम ओवरड्यू)

Ques: The Asian Development Bank (ADB) announced a \$70 billion plan for which sectors in the Asia-Pacific region?

प्रश्न: एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर की योजना किन क्षेत्रों के लिए घोषित की?

- A) Agriculture & Health / कृषि एवं स्वास्थ्य
- B) Education & Tourism / शिक्षा एवं पर्यटन
- C) Energy & Digital Infrastructure / ऊर्जा एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
- D) Defence & Space / रक्षा एवं अंतरिक्ष
- E) Banking & Finance / बैंकिंग एवं वित्त

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank announced a \$70 billion programme for energy and digital infrastructure.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70 बिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की।
- The announcement was made during the 59th Annual Meeting held in Samarkand, Uzbekistan.
- यह घोषणा समरकंद, उज़्बेकिस्तान में की गई।
- The plan aims to expand energy connectivity and digital networks across the Asia-Pacific region by 2035.
- इस योजना का उद्देश्य 2035 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार करना है।
- It includes \$50 billion for Pan-Asia Power Grid Initiative and \$20 billion for digital connectivity.
- इसमें 50 बिलियन डॉलर पावर ग्रिड और 20 बिलियन डॉलर डिजिटल कनेक्टिविटी के

लिए हैं।

- It will strengthen cross-border electricity trade and broadband access.
- यह सीमा-पार बिजली व्यापार और ब्रॉडबैंड पहुंच को मजबूत करेगा।
- ADB President Masato Kanda emphasized long-term economic growth.
- एडीबी अध्यक्ष Masato Kanda ने दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Asian Development Bank Established – 1966
- एडीबी की स्थापना – 1966
- Headquarters – Manila, Philippines
- मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस
- President – Masato Kanda (2026)
- अध्यक्ष – Masato Kanda (2026)
- Members – 69 Countries
- सदस्य – 69 देश
- Objective – Promote economic development and regional cooperation
- उद्देश्य – आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

Ques: National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), often referred to as India's "Bad Bank", was established in which year?

प्रश्न: नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), जिसे भारत का "बैड बैंक" कहा जाता है, किस वर्ष स्थापित की गई थी?

- A) 2018
- B) 2019
- C) 2020
- D) 2021
- E) 2022

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) is known as India's "Bad Bank".
- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को भारत का "बैड बैंक" कहा जाता है।
- It was established in the year 2021.
- इसकी स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी।
- A bad bank is a special institution created to deal with bad loans (NPAs) of banks.
- बैड बैंक एक विशेष संस्था होती है जो बैंकों के खराब ऋण (NPA) से निपटने के लिए बनाई जाती है।
- NARCL has accelerated its recovery efforts in FY 2025–26, recovering Rs. 4,364 crore during the year.
- NARCL ने वित्त वर्ष 2025–26 में अपनी रिकवरी प्रक्रिया तेज करते हुए 4,364 करोड़ रुपये की वसूली की।
- This accounts for nearly 70% of its total recoveries to date.
- यह अब तक की कुल वसूली का लगभग 70% है।
- Total cumulative recoveries by NARCL have reached Rs. 6,345 crore.
- NARCL द्वारा कुल संचयी वसूली 6,345 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
- The government-backed institution has acquired 33 borrower entities.
- सरकार समर्थित इस संस्था ने अब तक 33 उधारकर्ता संस्थाओं का अधिग्रहण किया है।
- These accounts have a total debt exposure of Rs. 1.65 lakh crore.
- इन खातों का कुल ऋण जोखिम 1.65 लाख करोड़ रुपये है।

Ques: Viability Plan 2.0 for RRBs focuses on how many key pillars?

प्रश्न: RRBs के लिए Viability Plan 2.0 कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित है?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

E) 6

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Financial Services (DFS) has approved Viability Plan 2.0 for Regional Rural Banks (RRBs) for FY 2025–26 to 2027–28.
- वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने FY 2025–26 से 2027–28 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए Viability Plan 2.0 को मंजूरी दी है।
- The plan includes 30 performance parameters structured across four key pillars — operational excellence, asset quality, profitability, and growth.
- इस योजना में 30 प्रदर्शन मानक शामिल हैं, जो चार मुख्य स्तंभों—ऑपरेशनल उत्कृष्टता, एसेट क्वालिटी, लाभप्रदता और वृद्धि—पर आधारित हैं।
- It aims to improve financial sustainability, strengthen recovery mechanisms, and enhance digital adoption in RRBs.
- इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बढ़ाना, रिकवरी प्रणाली को मजबूत करना और RRBs में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देना है।
- The plan replaces the earlier Viability Plan (FY22–FY25) and targets better governance and efficiency across all 28 RRBs.
- यह योजना पूर्व Viability Plan (FY22–FY25) का स्थान लेती है और सभी 28 RRBs में बेहतर गवर्नेंस और दक्षता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
- This initiative supports financial inclusion and strengthens rural banking infrastructure in India.
- यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और भारत में ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मजबूत करती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RRBs Established – 1975
- RRBs की स्थापना – 1975
- Regulated By – Reserve Bank of India (RBI) & NABARD
- विनियामक – RBI एवं NABARD
- Objective – Financial Inclusion in Rural Areas

- उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन
- Total RRBs – 28
- कुल RRBs – 28

Ques: What was the total UPI transaction value in April after a slight dip from March highs?

प्रश्न: मार्च के उच्च स्तर से गिरावट के बाद अप्रैल में UPI लेनदेन का कुल मूल्य कितना रहा?

- A) ₹28.50 trillion / ₹28.50 ट्रिलियन
- B) ₹29.03 trillion / ₹29.03 ट्रिलियन
- C) ₹29.53 trillion / ₹29.53 ट्रिलियन
- D) ₹30.10 trillion / ₹30.10 ट्रिलियन
- E) ₹27.90 trillion / ₹27.90 ट्रिलियन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- UPI transaction value dipped by 1.7% in April to ₹29.03 trillion.
- अप्रैल में UPI लेनदेन का मूल्य 1.7% घटकर ₹29.03 ट्रिलियन हो गया।
- In March, the transaction value was ₹29.53 trillion.
- मार्च में लेनदेन का मूल्य ₹29.53 ट्रिलियन था।
- UPI transaction volume declined by 1.3% to 22.35 billion in April.
- अप्रैल में UPI लेनदेन की मात्रा 1.3% घटकर 22.35 बिलियन हो गई।
- In March, the volume was 22.64 billion transactions.
- मार्च में लेनदेन की मात्रा 22.64 बिलियन थी।
- Year-on-year, April recorded a 25% rise in volume and a 21% increase in value.
- वर्ष-दर-वर्ष, अप्रैल में मात्रा में 25% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई।
- Despite the monthly dip, daily transaction volumes increased from 730

million in March to 745 million in April.

- मासिक गिरावट के बावजूद, दैनिक लेनदेन मात्रा मार्च के 730 मिलियन से बढ़कर अप्रैल में 745 मिलियन हो गई।
- The data is released by the National Payments Corporation of India (NPCI), which operates UPI.
- यह डेटा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किया जाता है, जो UPI का संचालन करता है।

Ques: What was India's net direct tax collection in the financial year 2025–26, as per CBDT data?

प्रश्न: CBDT के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Net Direct Tax) संग्रह कितना रहा?

- A) Rs. 21,40,406 crore / 21,40,406 करोड़ रुपये
- B) Rs. 22,50,000 crore / 22,50,000 करोड़ रुपये
- C) Rs. 23,40,406 crore / 23,40,406 करोड़ रुपये
- D) Rs. 24,10,000 crore / 24,10,000 करोड़ रुपये
- E) Rs. 25,00,000 crore / 25,00,000 करोड़ रुपये

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India's net direct tax collections grew by 5.12% year-on-year in FY 2025–26.
- वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष-दर-वर्ष 5.12% बढ़ा।
- The total net direct tax collection stood at Rs. 23,40,406 crore.
- कुल शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23,40,406 करोड़ रुपये रहा।
- Gross direct tax collections reached Rs. 28,11,936 crore, showing a growth of 4.03% over FY 2024–25.
- सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 28,11,936 करोड़ रुपये रहा, जो FY 2024–25 की तुलना में 4.03% अधिक है।

- Corporate tax collections increased to Rs. 13,81,606 crore.
- कॉर्पोरेट कर संग्रह बढ़कर 13,81,606 करोड़ रुपये हो गया।
- Non-corporate tax collections (including individuals, HUFs, firms, etc.) stood at Rs. 13,72,474 crore.
- गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह (व्यक्तियों, HUF, फर्म आदि) 13,72,474 करोड़ रुपये रहा।
- Securities Transaction Tax (STT) collections rose to Rs. 57,522 crore.
- सिक्क्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) संग्रह बढ़कर 57,522 करोड़ रुपये हो गया।

Ques: What was the non-food credit growth rate recorded by SCBs in FY 2025-26?

प्रश्न: FY 2025-26 में SCBs द्वारा दर्ज गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर क्या थी?

- A) 10.9%
- B) 12.5%
- C) 15.9%
- D) 18.2%
- E) 20%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Scheduled Commercial Banks (SCBs) recorded a strong 15.9% year-on-year non-food credit growth in FY 2025-26.
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने FY 2025-26 में 15.9% की वार्षिक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर्ज की।
- Total outstanding credit reached ₹212.9 lakh crore, increasing by ₹29.2 lakh crore over the previous year.
- कुल बकाया ऋण ₹212.9 लाख करोड़ पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹29.2 लाख करोड़ अधिक है।
- Growth was broad-based, led by services (19%), followed by personal loans (16.2%), industry (15%), and agriculture (15.7%).
- वृद्धि व्यापक रही, जिसमें सेवाएं (19%), पर्सनल लोन (16.2%), उद्योग (15%) और

कृषि (15.7%) प्रमुख रहे।

- Strong credit growth reflects improving economic activity, rising demand, and increased lending across sectors.
- यह मजबूत क्रेडिट वृद्धि बेहतर आर्थिक गतिविधि, बढ़ती मांग और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण विस्तार को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Regulator of Banks – Reserve Bank of India
- बैंकों का नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई

Ques: What was the total Goods and Services Tax (GST) collection of India in April 2026?

प्रश्न: अप्रैल 2026 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह कितना रहा?

- A) Rs. 2.10 lakh crore / 2.10 लाख करोड़ रुपये
- B) Rs. 2.25 lakh crore / 2.25 लाख करोड़ रुपये
- C) Rs. 2.33 lakh crore / 2.33 लाख करोड़ रुपये
- D) Rs. 2.42 lakh crore / 2.42 लाख करोड़ रुपये
- E) Rs. 2.50 lakh crore / 2.50 लाख करोड़ रुपये

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India's GST collections reached an all-time high of Rs. 2.42 lakh crore in April 2026.

- अप्रैल 2026 में भारत का GST संग्रह 2.42 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- This is the highest-ever monthly GST collection recorded in India.
- यह भारत में अब तक का सबसे अधिक मासिक GST संग्रह है।
- In April 2025, GST collection was Rs. 2.33 lakh crore.
- अप्रैल 2025 में GST संग्रह 2.33 लाख करोड़ रुपये था।
- The Year-on-Year (YoY) growth in April 2026 is 8.7%.
- अप्रैल 2026 में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि 8.7% रही।
- The increase reflects strong economic activity and improved compliance.
- यह वृद्धि मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर अनुपालन को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- GST Implemented – 1 July 2017
- GST लागू – 1 जुलाई 2017
- GST is an indirect tax replacing multiple taxes like VAT, Service Tax, Excise Duty
- GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने VAT, सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसे कई करों को प्रतिस्थापित किया
- GST Council Chairman – Union Finance Minister
- GST परिषद के अध्यक्ष – केंद्रीय वित्त मंत्री

Ques: What are Electronic Gold Receipts (EGRs) launched by the National Stock Exchange (NSE)?

प्रश्न: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा लॉन्च किए गए Electronic Gold Receipts (EGRs) क्या हैं?

- A) Digital currency backed by RBI / RBI द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा
- B) Electronic records representing ownership of physical gold / भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
- C) Gold mining licences / स्वर्ण खनन लाइसेंस

- D) Cryptocurrency linked with gold / सोने से जुड़ी क्रिप्टोकॉर्सेसी
E) Gold loan certificates / गोल्ड लोन प्रमाणपत्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- National Stock Exchange (NSE) has launched Electronic Gold Receipts (EGRs) as a new instrument for gold trading in India.
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने भारत में सोने के व्यापार के लिए Electronic Gold Receipts (EGRs) लॉन्च किए हैं।
- EGRs are electronic records representing ownership of physical gold stored in approved vaults.
- EGRs स्वीकृत वॉल्ट्स में रखे गए भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं।
- NSE demonstrated the dematerialisation of a 1000-gram gold bar into an Electronic Gold Receipt.
- NSE ने 1000 ग्राम सोने की बार को Electronic Gold Receipt में डिमैटेरियलाइज करने का प्रदर्शन किया।
- EGRs are dematerialised securities and are held electronically in demat accounts.
- EGRs डिमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज हैं और इन्हें डिमैट खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाता है।
- The gold backing EGRs is stored in SEBI-accredited vaults.
- EGRs के पीछे का सोना SEBI-मान्यता प्राप्त वॉल्ट्स में रखा जाता है।
- Each EGR is fully backed by real physical gold.
- प्रत्येक EGR पूरी तरह वास्तविक भौतिक सोने द्वारा समर्थित होता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- National Stock Exchange of India Limited Founded – 27 November 1992
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना – 27 नवंबर 1992
- Headquarters – Mumbai, Maharashtra

- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- MD and CEO – Ashish Kumar Chauhan
- एमडी और सीईओ – आशीष कुमार चौहान

Ques: Under the RBI's updated regulatory framework, after how many days from the due date will a credit card account be marked as "past due"?

प्रश्न: RBI के नए नियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाते को देय तिथि के कितने दिनों बाद "पास्ट ड्यू" माना जाएगा?

- A) 1 day / 1 दिन
- B) 2 days / 2 दिन
- C) 3 days / 3 दिन
- D) 5 days / 5 दिन
- E) 7 days / 7 दिन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has introduced a 3-day grace period for credit card payments.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए 3 दिन की ग्रेस अवधि शुरू की है।
- A credit card account will be marked as "past due" only after 3 days from the due date.
- क्रेडिट कार्ड खाते को देय तिथि के 3 दिन बाद ही "पास्ट ड्यू" माना जाएगा।
- Earlier, accounts could be classified as overdue immediately after the due date.
- पहले खातों को देय तिथि के तुरंत बाद ओवरड्यू माना जा सकता था।
- Banks can impose late payment charges and report to credit bureaus only after the 3-day grace period.

- बैंक 3 दिन की ग्रेस अवधि के बाद ही लेट फीस लगा सकते हैं और क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट कर सकते हैं।
- The new rule will come into effect from 1 April 2027.
- यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।
- If payment is made within the grace period, there will be no immediate penalty or negative credit reporting impact.
- यदि भुगतान ग्रेस अवधि के भीतर कर दिया जाता है, तो कोई तत्काल जुर्माना या नकारात्मक क्रेडिट रिपोर्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- Under revised norms, penalties will apply only on the outstanding amount and not on the total billed amount.
- संशोधित नियमों के तहत जुर्माना केवल बकाया राशि पर लगाया जाएगा, पूरे बिल की राशि पर नहीं।

Ques: S&P Global has reduced India's GDP growth forecast for Financial Year 2026–27 to what percentage?

प्रश्न: S&P Global ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है?

- A) 5.8%
- B) 6.2%
- C) 6.6%
- D) 7.0%
- E) 7.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- S&P Global lowered India's growth forecast for Financial Year 2026–27 by 50 basis points to 6.6 per cent.
- S&P Global ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया।

- The findings were published in a report titled “India Forward”.
- यह जानकारी “India Forward” नामक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई।
- The report was jointly prepared by S&P Global and Crisil.
- यह रिपोर्ट S&P Global और Crisil द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई।
- According to the report, India is facing external economic shocks.
- रिपोर्ट के अनुसार भारत बाहरी आर्थिक झटकों का सामना कर रहा है।
- These challenges include energy supply disruptions, rising oil and gas prices, and currency volatility.
- इन चुनौतियों में ऊर्जा आपूर्ति में बाधा, तेल और गैस की बढ़ती कीमतें तथा मुद्रा विनिमय दर में अस्थिरता शामिल हैं।
- A basis point is one-hundredth of a percentage point.
- एक बेसिस पॉइंट, प्रतिशत के सौवें हिस्से के बराबर होता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- S&P Global Headquarters – New York, United States
- S&P Global का मुख्यालय – न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
- CRISIL Full Form – Credit Rating Information Services of India Limited
- CRISIL का पूर्ण रूप – क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
- Crisil Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- Crisil का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

Ques: What percentage of the Reserve Bank of India's (RBI) total gold holdings is now stored within India as of March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कुल स्वर्ण भंडार का कितना प्रतिशत भारत में संग्रहीत है?

- A) 65%
- B) 70%
- C) 77%
- D) 82%
- E) 85%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Around 77% of RBI's total gold holdings is now stored within India.
- RBI के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 77% अब भारत में संग्रहीत है।
- RBI moved 104.23 metric tonnes (MT) of gold reserves domestically in the six months ended March 2026.
- मार्च 2026 तक के छह महीनों में RBI ने 104.23 मीट्रिक टन सोना भारत में स्थानांतरित किया।
- The move reflects a continued shift toward domestic gold custody.
- यह कदम घरेलू स्वर्ण भंडारण की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
- RBI's total gold holdings increased slightly to 880.52 MT in March 2026.
- मार्च 2026 में RBI का कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गया।
- According to RBI data, 197.67 MT of gold is kept with the Bank of England and the Bank for International Settlements (BIS).
- RBI के अनुसार 197.67 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास रखा गया है।
- Another 2.80 MT is maintained as gold deposits.
- अतिरिक्त 2.80 मीट्रिक टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है।
- In FY 2025–26, RBI brought 168.06 MT of gold back to India.
- वित्त वर्ष 2025–26 में RBI ने 168.06 मीट्रिक टन सोना भारत वापस लाया।
- This is higher than 107.21 MT in 2023–24 and 103.68 MT in 2024–25.
- यह 2023–24 के 107.21 मीट्रिक टन और 2024–25 के 103.68 मीट्रिक टन से अधिक है।